



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 526]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1995/पौष 4, 1917

No. 526]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1995/PAUSA 4, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1995

आयकर

अनुबंध

आय तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए

भारत गणराज्य

और

साइप्रस गणराज्य

के बीच करार

आय तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए

भारत गणराज्य

और

साइप्रस गणराज्य

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा साइप्रस गणराज्य की सरकार,

आय तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए एक करार सम्पन्न करने की इच्छा से; निम्नानुसार सहमत हुई:—

सा.का.नि. 805(अ).—चूंकि आय कर पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और साइप्रस गणराज्य की सरकार के बीच सम्पन्न संलग्न करार, उक्त करार के अनुच्छेद-30 के पैरा 1 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यविधियों को पूरा करने के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित कर देने के पश्चात् दिनांक 21-12-1994 से प्रवृत्त हो गया है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अध्याय—I

करार का विषय-क्षेत्र

अनुच्छेद—1

वैयक्तिक-क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद—2

इस करार के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह करार उन सभी करों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों अथवा उसके राजनीतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय निकायों की ओर से आय तथा पूँजी पर लगाये जाते हैं, इस बात को छोड़कर कि वे किस प्रकार लगाये जाते हैं।

2. सकल आय, सकल पूँजी अथवा आय अथवा पूँजी के तत्त्व पर लगने वाले सभी कर आय तथा पूँजी पर लगने वाले करों के रूप में माने जायेंगे, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अनुलाभों पर लगने वाले करों, उद्यमों द्वारा अदा किये गये पगार तथा वेतनों की सकल रकम पर लगने वाले कर तथा साथ ही पूँजी वृद्धि पर लगने वाले करों की राशि भी शामिल है।

3. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:

- (क) भारत के मामले में:
 - (i) आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;
 - (ii) धनकर;
 - (जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जायेगा);
- (ख) साइप्रस के मामले में
 - (i) आयकर;
 - (ii) निगमित आयकर;
 - (iii) विशेष अंशदान;
 - (iv) पूँजीगत अभिलाभ कर;
 - (v) अचल परिसम्पत्ति कर;
 - (जिन्हें इसके बाद "साइप्रस कर" कहा जायेगा)।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा मौजूदा करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ 3 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाये जायेंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में हुए मूल परिवर्तनों की सूचना एक-दूसरे को देंगे।

अध्याय—II

परिभाषाएँ

अनुच्छेद—3

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "भारत" पद से अभिप्रेत है—भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों/समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र अभिसन्ध के कानून अनुसार भारत के प्रभु-सत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) "साइप्रस" पद से अभिप्रेत है—साइप्रस गणराज्य जिसमें उसका राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्रीय समुद्र, महा-द्वीपीय खण्ड तथा कोई ऐसा अन्य क्षेत्र शामिल है जिस पर अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा जिस पर साइप्रस के कानून लागू हैं तथा इसके पश्चात् ऐसा नामित क्षेत्र जिस पर साइप्रस गणराज्य के सम्प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा उसके कर्तव्य हों;

(ग) "संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा साइप्रस अभिप्रेत है;

(घ) "कम्पनी" पद से ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई भी ऐसी सत्ता-अभिप्रेत है, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत किसी कंपनी अथवा निगमति निकाय के रूप में मानी जाती हो;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" पद का आशय,—भारत के मामले में केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्राधिकारी, तथा साइप्रस के मामले में वित्त मंत्री तथा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि है;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पद से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(छ) "वित्त वर्ष" पद से अभिप्रेत है:

- (i) भारत के मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत परिभाषित "पूर्ववर्ती वर्ष";
- (ii) साइप्रस के मामले में, व्यावसायिक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 में परिभाषित "कर निर्धारण वर्ष";

(ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है— किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई ऐसा परिवहन जो किसी संविदाकारी राज्य के पंजीकृत उद्यम तथा मुख्यालय (अर्थात् प्रभावी प्रबंध) द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के म्पानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(झ) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है:

- (i) भारत के मामले में, राष्ट्रीयता धारण करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति और किसी ऐसे विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था अभिप्रेत है—जिसे अपनी यह हैसियत भारत में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त हो;
- (ii) साइप्रस के मामले में, नागरिकता धारण करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति और किसी ऐसे विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था अभिप्रेत है जिस अपनी यह हैसियत भारत में प्रवृत्त कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त हो;

(ञ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत कर लगाने योग्य इकाई माना जाता हो;

(ट) "कर" पद से अभिप्रेत है, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा साइप्रस कर, परन्तु ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो करों के संबंध में किसी भूक अथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिस पर यह करार लागू होता हो अथवा करों के संबंध में लगाया गया कोई व्ययदण्ड हो।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद—4

अनिवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है—काई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसोटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है, परन्तु इस पद में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में उस राज्य के खोले से अथवा उसमें अवस्थित पूंजी से होने वाली केवल आय के संबंध में कर संदेय है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जायेगी:—

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) है;

(ख) यदि उस राज्य जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां ध्याष्ट से मिश्र कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-संस्थान स्थित है।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं:—

- (क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;

(छ) कोई भवन-स्थल, कोई निर्माण-कार्य, कोई संयोजन परियोजना, संस्थापना परियोजना, उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप केवल वहां जहां ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप बारह मास से अधिक की अवधि तक चलते रहें।

3 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा:—

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल फ्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ.) उद्यम के लिए अनन्य रूप से विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा उसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में, जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना। तथापि, यह उपबंध वहां लागू नहीं होगा जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्यम व्यापार का कोई अन्य नियत स्थान रखता हो;
- (च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) में उल्लिखित कार्य-कलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान के होने वाले समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा सहायक रूप के हों।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के एजेंट से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, किसी उद्यम की ओर से कार्य करता है तथा वह उद्यम की ओर से करार निष्पन्न करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य में आश्रित अपने प्राधिकार का प्रयोग करता है और करता रहा है, तो उस उद्यम का, ऐसे कार्यकलापों के संबंध में जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना समझा जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति की

गतिविधियां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित नहीं हों, यदि कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उद्यम दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

6. यदि कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी भी ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी एक कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अध्याय - III

आय का कराधान

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उप-साधन के रूप में सम्पत्ति, उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नावें, विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल संपत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है। किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता है :

- (क) उस स्थायी संस्थापन ;
- (ख) उस दूसरे राज्य में एक-समान अथवा उसी प्रकार के माल अथवा पण्य-वस्तुओं की विक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है; अथवा
- (ग) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार संबंधी वैसी ही अथवा मिलती-जुलती अन्य गति-विधियां जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती हों।

उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (ख) और (ग) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उद्यम यह सिद्ध करता है कि ऐसी विक्री अथवा गतिविधि स्थायी संस्थापन द्वारा उचित रूप से नहीं की जा सकी है।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे, जिनके होने की अपेक्षा रहती, जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन खर्चों की कटौतों की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं। भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा

यह उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों की सीमाओं के अधीन किए गए हों।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर किसी स्थायी संस्थापन के माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ (2) की कोई भी व्यवस्था ऐसे संविदाकारी राज्य की ऐसी प्रचलित प्रभाजन पद्धति से, कर लगने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी। तथापि, अपनार्थ गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित मिद्दातों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने, उद्यम के लिए मान्य अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें भी शामिल हों, जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां इन अनुच्छेद के उपबंध इन अनुच्छेदों के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी पंजीकृत उद्यम तथा उसके मुख्यालय (अर्थात् प्रभावी प्रबन्ध) द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में जहाजरानी अथवा वायु परिवहन के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभों का तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित समुद्र अथवा वायुमार्ग वाले जलयान अथवा वायुयान के स्वामी अथवा पट्टेदार अथवा चार्टरर के द्वारा यात्रियों, डाक, पशु-धन अथवा माल के परिवहन से प्राप्त लाभ से होगा और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) दूसरे उद्यम की ओर से ऐसे परिवहन के लिए बेचे गए टिकट;
- (ख) ऐसे परिवहन में प्रत्यक्षतः संबंधित अन्य कार्य-कलाप;
- (ग) किराए के जलयान अथवा वायुयान के किसी परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्य-कलाप।

3. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के परिचालन में प्रत्यक्षतः संबद्ध उसके उपयोग, रख-रखाव अथवा किराए के आधानों (ट्रेलर्स, बर्गेज तथा आधानों के परिवहन में संबद्ध उपस्कर सहित) से प्राप्त लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगेंगा।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान अथवा जलयानों से संबंधित प्रचालन से जुड़ी हुई निधियों पर व्याज को ऐसे विमान अथवा जलयानों के प्रचालन से प्राप्त हुए लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे (व्याज) के मामले में लागू नहीं होंगे।

6. पैराग्राफ 1 में यथा-उल्लिखित किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का कोई ऐसा जनयान, वायुयान अथवा आधान जो उसके स्वामित्व में हो और उसके द्वारा प्रचालित किया गया हो, के प्रवर्तन से प्राप्त लाभों पर, जिन पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है, उन पर उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां :

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो वहां ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों में नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु, उन शर्तों के कारण, इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, वे लाभ, उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी, बिकल्प का प्रयोजन करते हुए ऐसी देनदारी का निर्धारण करने, और जिन मामलों में किसी उद्यम को प्राप्त होने वाली, समझी जाने वाली आय

का निर्धारण करना संभव अथवा व्यावहारिक न हो, ऐसे मामलों में उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध सूचना के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमान लगाने से संबंधित संविदाकारी राज्य के किसी कानून को प्रभावित नहीं करेगा बशर्ते कि जहां तक कि सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना की अनुमति दे, इस अनुच्छेद के सिद्धांतों के अनुरूप कानून को लागू किया जाए।

3. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है—जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमो-लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें इस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभाविता कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इसके अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

- (क) लाभांश की सकल रकम का 10 प्रतिशत, यदि हितभागी-स्वामी ऐसी कम्पनी है जिसके पास लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के काम से कम 10 प्रतिशत शेयर हों;
- (ख) दूसरे मामले में लाभांश की सकल रकम का 15 प्रतिशत।

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इन सीमाओं को लागू करने के तरीके का निर्णय करेंगे।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ प्रायः शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो

लाभ की भागीदारी के ऋण-दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभार्थी का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिनकी लाभार्थी अदा करने वाली कम्पनी, एक निवासी है अथवा उभे दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभार्थी की अदायगी की जाती है, वहाँ वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्भव है। ऐसे मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभार्थी पर वहाँ तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहाँ तक कि ऐसे लाभार्थी उभे दूसरे राज्य के निवासी की अदा किए जाते हैं अथवा जहाँ तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभार्थी की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, वहाँ उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभार्थी अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद - 11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर व्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी :

(क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए व्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि

वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा उनके हितभागी स्वामित्व में हो :

(i) इस संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा

(ii) उस दूसरे राज्य का सेंट्रल बैंक अथवा कोई एजेंसी अथवा किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाला परिकरण (वित्तीय संस्थान सहित)

(ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में उतनी सीमा तक कर से छूट दी जाएगी, जितनी उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हो, यदि वह उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से भिन्न, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा उसके हितभागी-स्वामित्व में हो तो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, बशर्ते कि जिस लेन-देन से ऋण-दावे उत्पन्न हुए, उन्हें प्रथमोसिलखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा उस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज" पद से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के इस प्रयोजन के लिए व्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज का हितभागी-स्वामी जो संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जितने व्याज उद्भूत हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उभे दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस ऋणदावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो, ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ नहीं माना जाएगा, जब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य उस संविदाकारी राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो।

किन्तु, जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह श्रृण लिया गया था, जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का व्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ, व्याज अदाकर्ता तथा हितधिकारी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई व्याज की रकम, उस श्रृण-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए व्याज की यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितधिकारी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस प्रकार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुरार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियाँ और फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियों और फीस के लिए उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, सम्मिलित सेवाओं के लिए ऐसी रायल्टियों और फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिनमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुरार कर लगाया जा सकेगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियाँ अथवा फीस का हितभागी स्वामी हो, तब इस प्रकार प्रभारित कर सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियों और फीस की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "रायल्टियों" पद से अदायगियाँ अथवा क्रेडिट अभिप्रेत हैं, चाहे ये आवधिक हों या नहीं और तथापि, इनका वर्णन अथवा संगणना कैसे भी की गयी हो और जिस सीमा तक प्रतिकल के रूप में दिए गए हो वे निम्नलिखित हैं :

(क) किसी प्रयोगाधिकार अथवा वापरीराइट का अर्थात् कोई पेटेंट, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुण फार्मुला अथवा प्रक्रिया, ट्रेड मार्क अथवा अन्य ऐसी सम्पत्ति अथवा अधिकार;

(ख) उपयोग अथवा प्रयोगाधिकार, किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग;

(ग) वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक जानकारी अथवा सूचना की आपूर्ति,

(घ) निम्नलिखित का उपयोग अथवा प्रयोगाधिकार:

(i) चल-चित्र फिल्में;

(ii) टेलीविजन से संबंधित प्रयोग के लिए फिल्में अथवा वीडियो-टैपें;

(iii) रेडियो प्रसारण के संबंध में प्रयोग हेतु रेडियो टैपें; अथवा

(ङ.) इस पैराग्राफ में उल्लिखित किसी सम्पत्ति अथवा अधिकार के प्रयोग अथवा सप्लाय के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक परिहार।

4. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस" पद का अर्थ भुगतानों अथवा क्रेडिटों से है, चाहे ये आवधिक हों या नहीं, और इनका वर्णन अथवा संगणना कैसे भी की गयी हो तथा इनका किस सीमा तक निम्नलिखित के लिए प्रतिकल के रूप में भुगतान किया गया हो:

(क) कोई ऐसी सहायता सप्लाय करना जो गौण अथवा सहायक हो और जो पैराग्राफ 3 के उपपैराग्राफ

(क) में उल्लिखित ऐसी किसी सम्पत्ति अथवा अधिकार को लागू करने अथवा उसका प्रयोग करने के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, ऐसा कोई उपकरण जो पैराग्राफ (3) के उप-पैराग्राफ (ख) में उल्लिखित हो, अथवा पैराग्राफ (3) के उप-पैराग्राफ (ग) में उल्लिखित कोई ऐसी जानकारी अथवा सूचना;

(ख) कोई तकनीकी अथवा परामर्शदायी सेवाएं उपलब्ध कराना (तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों के उपबंध सहित) यदि ऐसी सेवाओं द्वारा तकनीकी जानकारी, अनुभव, महारथ ज्ञान अथवा प्रक्रिया उपलब्ध करायी जाती है अथवा इसमें तकनीकी प्लान अथवा तकनीकी डिजाइन का विकास और अन्तरण शामिल है।

5. पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियों और फीसों का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें सम्मिलित सेवाओं के लिए रायल्टियाँ अथवा फीस उद्भूत होती है, वहाँ पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में सम्मिलित सेवाओं के संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा किए जाते हैं, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

6. एक संविदाकारी राज्य में सम्मिलित सेनाओं के लिए रायल्टियां और फौजदार उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उसका कोई निवासी हो। तथापि, जहां सम्मिलित सेनाओं के लिए रायल्टियां अथवा फीस अदा करने वाला व्यक्ति चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टियां अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस की रकम, इसके उपयोग, अधिकार तथा सूचना जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी, उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी-स्वामी के बीच सहमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगाया जाना रहेगा।

अनुच्छेद-13

तकनीकी फीस

4. किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तकनीकी फीस जो अन्य संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्राप्त होती है, पर उस अन्य राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, ऐसी तकनीकी फीस पर भी उस संविदाकारी राज्य में, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उद्भूत होती है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी फीस का हितभागी-स्वामी हो, इस प्रकार प्रभारित कर की रकम तकनीकी फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी फीस" पद का अर्थ, किसी तकनीकी प्रबन्धकीय अथवा परामर्शदायी किस्म की सेवाओं के लिए प्रतिकूल के रूप में अदायगियां करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी को छोड़कर किसी व्यक्ति को अदा की गयी किसी भी प्रकार की अदायगियों से है।

4. पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं का हितभागी-स्वामी,

जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते उस अन्य संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस अन्य राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पन्न करता है और तकनीकी फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा ऐसी सेवाओं से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में, यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. किसी एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब कर अदा करने वाला वह स्वयं राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई सांविधिक निकाय अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी फीस अदा करने वाला व्यक्ति, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, का एक संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन हो जिसके संबंध में तकनीकी फीस अदा करने का वचन दिया गया था, तथा ऐसी तकनीकी फीस उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन की गयी थी, तब ऐसी तकनीकी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो।

6. जहां, अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता अथवा उन दोनों के बीच और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी तकनीकी फीस की रकम किसी कारण से उस रकम से बढ़ जाती है जिसके बारे में इस संबंध में न होने पर अदाकर्ता तथा हितभागी-स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, तब इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत, इस समझौते के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, कर देय होगा।

अनुच्छेद-14

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अवल सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारखाना सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों से संबंधित चल-संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध-स्थान स्थित हो।

4. पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न, किसी भी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद-15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा अन्य स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संगत वित्त वर्ष में, कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक हों, तो यथा-स्थिति के अनुसार आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं", पद में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद-16

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 19, 20, 21 और 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य

में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत वित्त वर्ष के दौरान, ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा हो जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है ;

(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजन द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित पोत अथवा विमान पर दिए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध-स्थान स्थित हो।

अनुच्छेद-17

निदेशकों की फीस

1. निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक-मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गयी हो, उन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद-18

कलाकारों तथा खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूर दर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक

कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता वा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस पर अनुच्छेद 7, 17 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोल्लिखित राज्य की, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित होते हैं।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियत में एक संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्ता अथवा स्वयं खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है, परन्तु किसी अन्य को प्राप्त होती है तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर योग्य होगी, यदि वह अन्य व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो, जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित होते हैं।

अनुच्छेद-19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :

- (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा
- (ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए

की गयी सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

(ख) लेकिन, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तब लग सकेगा यदि व्यक्ति उस अन्य राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 16, 17 तथा 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-20

गैर सरकारी पेंशन तथा वार्षिकियां

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्त्रोतों से प्राप्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किसी पेंशन अथवा किसी वार्षिकी पर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

2. "पेंशन" पद से पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई शारीरिक क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की गई आबधिक अदायगी अभिप्रेत है।

3. "वार्षिकी" पद के जीवन-काल में अथवा किसी निनिर्दिष्ट या अनिश्चित समयावधि के दौरान धन-राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी करने के इस्तेमाल के अंतर्गत आबधिक रूप से निश्चित समय पर अदायगी-योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है।

अनुच्छेद-21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में जाने के तुरन्त पूर्व, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था, और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, उसे उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उस दूसरे राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गयी अदायगियों पर ; और

(ख) उस अन्य राज्य में नियोजन से पारिश्रमिक, उस राशि में जो किसी भी वित्त वर्ष के दौरान 5,000 अमरीकी डालरों अथवा उसके समकक्ष राशि से अधिक न हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययनों से सीधे संबंधित हो अथवा उसके अपने भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ हो।

2. इस अनुच्छेद के उप-पैराग्राफ (ख) के पैराग्राफ (1) का लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए दिया जाएगा जो शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा सामुदायिकता अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में, किसी भी व्यक्ति को उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रथम बार पहुंचने की तारीख से लगातार तीन वर्ष से अधिक के लिए इस अनुच्छेद के उप-पैराग्राफ (ख) के पैराग्राफ (1) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद-22

प्राध्यापकों, अध्यापकों और शोध-छात्रों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक, जो किसी संविदाकारी राज्य के दौरान करने के तुरन्त पूर्व अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तथा जो उच्च अध्ययन अथवा किसी विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ प्रमोदित लिखित राज्य में दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए मौजूद हो, को ऐसे कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि उसे ऐसा पारिश्रमिक उस राज्य के बाहर प्राप्त हुआ हो।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध-कार्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह उस वित्त वर्ष में अथवा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के तुरन्त बाद उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो जिसमें वह अन्य संविदाकारी राज्य का दौरा करता है।

अनुच्छेद-23

अन्य आय

1. पैराग्राफ (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदें जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया हो, केवल उस राज्य में कराये होगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन

अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, क संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

अनुच्छेद-24

पूँजी

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा धारित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित, अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति वाली पूँजी पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार-सम्पत्ति का हिस्सा बनने वाली चल-संपत्ति के रूप में निरूपित पूँजी जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाई गई हो, अथवा किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल संपत्ति को निरूपित करने वाली पूँजी पर, स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित जलयानों और वायुयानों और ऐसे जलयानों और वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल संपत्ति को निरूपित करने वाली पूँजी पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिस स्थान पर उस उद्यम की प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था स्थापित है।

4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूँजी के अन्य सभी हिस्सों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

अध्याय 4

दोहरे कराधान के अपकरण के लिए पद्धतियाँ

अनुच्छेद-25

दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय और पूँजी के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे सिवाय ऐसे मामलों के जहां पर इस करार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध किया गया हो।

2. जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामी हो जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार साक्ष्य में कर लगेगा, वहां भारत, चाहे प्रत्यक्ष

रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर साइप्रस में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा, और साइप्रस में उस निवासी की पूंजी पर अदा किए गए पूंजी कर की राशि किसी भी मामले में अथवा अथवा पूंजी कर (कटौती किए जाने से पूर्व यथा-संगणित) के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसी आय, अथवा पूंजी, जैसा भी मामला हो, के कारण हो, जिस पर साइप्रस में कर लगाया जा सकता है।

3. साइप्रस के मामले में, साइप्रस के क्षेत्र से बाहर देय-कर के लिए साइप्रस-कर के प्रति क्रेडिट के रूप में स्वीकार करके साइप्रस के कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए दोहरे कराधान का परिहार किया जाएगा। भारत के भारत के स्त्रोतों से लाभों, आय अथवा धनिकत्यों के संबंध में भारत के कानूनों के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा कटौती द्वारा देय भारतीय-कर उस लाभ, आय अथवा लाभों के संबंध में देय किसी भी साइप्रस-कर के प्रति क्रेडिट के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। तथापि, ऐसी कटौती कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसकी कटौती देने से पहले गणना की गई हो, जो कि भारत में प्राप्त की गई आय के उपयुक्त हो।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्यों में देय कर में वह देय कर भी शामिल समझा जाएगा जो कि संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रदान किए गए कर प्रोत्साहनों और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं, के कारण अदा नहीं किया गया है अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 के प्रयोजन के लिए कर की राशि लाभों की सकल राशि का 10 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, समझी जाएगी। अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 के प्रयोजन के लिए कर की राशि व्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत होगी और अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 के प्रयोजन के लिए कर की राशि गयल्टियों और गारंजित सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत मानी जाएगी और अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 के प्रयोजन के लिए कर की राशि तकनीकी फीस की सकल राशि का 10 प्रतिशत समझी जाएगी।

5. जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार जहां एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गयी आय उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है वहां ऐसा राज्य, ऐसे निवासी की वसूली आय पर कर की रकम की संग्रहण करने में, छूट-प्राप्त आय को हिसाब में ले सकता है।

अध्याय V

विशेष उपबंध

अनुच्छेद - 26

नाम - व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य से ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उस संविदा अधेष्टाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो जो दूसरे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर समान परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में समान कार्यकलापों के लिए एक समान परिस्थितियों में लगे हुए उद्यमों पर लगाया जाता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकता है जो कि उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के उसी प्रकार के लाभों पर लगाई जाती है और न ही इस प्रकार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्य-कर है कि वह उन व्यक्तियों को जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, पर प्रयोजनों के लिए किसी की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत, कटौतियाँ और कटौतियाँ मंजूर करे, जो कानून द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध है जो वहां के निवासी हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तत्संबंधी किसी भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" पद से अभिप्राय, इस करार में यथा-निर्दिष्ट प्रत्येक विषय के करों से है।

अनुच्छेद - 27

पारस्परिक करार कार्य-विधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्य-विधियों के कारण इस प्रकार का कर लगाया जाएगा जो कि

इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय कानून में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह मामला उस कार्यवाही का नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके कारण कर लगाया गया था जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा निर्धारित हो।

3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाई अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। दोहरे कराधान को दूर करने के लिए, उन मामलों में, जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गयी है, एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों को ध्यान में रखकर समझौते पर पहुंचने के लिए एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उपयुक्त हो तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

अनुच्छेद - 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का दस्तावेजों सहित आदान-प्रदान करेंगे, जो इस करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित करार के उपबंधों अथवा आन्तरिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है जो इस करार के अन्तर्गत आते हैं जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो, विशेष रूप से ऐसे करों की घोषणा अथवा अपवर्जन को रोका जा सके। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गयी कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानून के अन्तर्गत प्राप्त की गयी सूचना मानी जाती है और यह सूचना केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को प्रकट की जाएगी जो करार में शामिल उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी धसूली करने, उनके प्रवर्तन

अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबंध हों। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपरोक्त करेंगे। वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट का सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों को और तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा जिसमें जहां कहीं उपयुक्त हो, कर अपवर्जन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो किसी नेमी आधार पर स्वतः किया जा सकता है अथवा मामले विशेष अथवा दोनों के संदर्भ में अनुरोध करने पर किया जायेगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उस सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर समय-समय पर सहमत होंगे जो किसी नेमी आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :—

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रणामन को सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक तथा कौंसली अधिकारी

1. इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कौंसली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय - VI

अन्तिम उपबन्ध

अनुच्छेद - 30

प्रवर्तन

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य एक दूसरे को यह सूचना देगा कि उन्होंने इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपने

अपने कानून द्वारा अपेक्षित कार्य विधियां पूरी कर ली हैं। यह करार इन अनुसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा :—

(क) भारत में, वर्ष 1993 के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और वर्ष 1993 के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर धारित-पूँजी के संबंध में।

(ख) साइप्रस में, वर्ष 1993 के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और वर्ष 1993 के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी वित्त वर्ष की समाप्ति पर धारित पूँजी के संबंध में।

अनुच्छेद-31

समापन

1. यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा, परन्तु दोनों में से कोई भी एक संबिदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पूरा हो जाने के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष के जून मास की तीस तारीख को अथवा इससे पहले राजनयिक माध्यम से दूसरे संबिदाकारी राज्य को करार के समापन की लिखित तौर पर सूचना दे सकता है तथा ऐसी परिस्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष अप्रैल मास की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और जिस कैलेंडर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात् होने वाले वित्त वर्ष के अंत में धारित-पूँजी के संबंध में,

(ख) साइप्रस में, जिस कैलेंडर वर्ष में सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में और जिस कैलेंडर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के वित्त-वर्ष के अंत में धारित पूँजी के संबंध में।

जिसके साक्ष में, इसके लिए विशिष्ट रूप में प्राधिकृत अधिकारियों ने उस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

निकोशिया में वर्ष एक हजार नौ सौ चरानबे जून के मास के तेरहवें दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में निष्पन्न किया गया, तथा ये सभी पाठ सामान रूप से प्रामाणिक हैं। इन पाठों में से किसी भी पाठ में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

योगेश तिवारी

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

ह. अपठनीय

साइप्रस गणराज्य की

सरकार की ओर से

[संख्या 9930/95 F No. 503/4/89-FTO]

वी. बी. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1995

Income-tax

GSR 805(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Cyprus for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on income has entered into force on 21-12-94, after the notification by both the contracting States to each other of the completion of the procedures required by their laws for bringing into force the said Agreement in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income Tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

Agreement between the Republic of India and the Republic of Cyprus

For the avoidance of double taxation and the prevention of Fiscal evasion with respect to taxes on Income and on Capital.

AGREEMENT

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE REPUBLIC OF CYPRUS

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of INDIA and the Government of the Republic of CYPRUS DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, HAVE agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) in India:

(i) the income tax including any surcharge thereon;

(ii) the wealth tax;

(herein after referred to as "Indian tax");

(b) in Cyprus:

(i) the income tax;

(ii) the corporate income tax;

(iii) the special contribution;

(iv) the capital gains tax;

(herein after referred to as "Cyprus tax")

4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Articles

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian Law and in accordance with international law/the U.N. Convention on the Law of the Sea.

(b) the term "Cyprus" means the Republic of Cyprus including the national territory, the territorial sea, the continental shelf, and any other areas which in accordance with international law and the law of the Republic of Cyprus has been for may hereafter be designated as an area within which the Republic of Cyprus exercises sovereign rights or has jurisdiction or any other rights and duties;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Cyprus as the context requires;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(e) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Cyprus, the Minister of Finance or his authorised representative;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "fiscal year" means:

(i) in the case of India, previous year as defined under Section 3 of the Income Tax Act 1961;

(ii) in the case of Cyprus, "year of a assessment" as defined under Section 2 of the Income Tax Law 1961 as amended;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise registered and having the headquarters (i.e. effective management) in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(i) the term "national" means:

(i) in the case of India, any individual possessing the nationality of India and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in India;

(ii) in the case of Cyprus, individuals possessing the citizenship of Cyprus and any person other than an individual deriving its status as such from the laws in force in Cyprus;

(j) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(k) the term "tax" means Indian tax or Cyprus tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which this Agreement applies.

ARTICLE 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include a person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or on capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows,

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interest cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a building site, construction assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activity continues for a period of more than twelve months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise. However, this provision shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purpose or purposes other than the purposes specified in this paragraph.
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provide that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies is acting on behalf of enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker,

general commission agent or any other agent of an independent status provided that such person is acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The act that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting state may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other contracting State through a permanent establishment situated there in. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in

other state but only so much of them as is attributable to:

- (a) that permanent establishment;
- (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or
- (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

The provisions of sub-paragraphs (b) and (c) above shall not apply if the enterprise proves that such sale or activity could not have been reasonably undertaken by the permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributable to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere in accordance with the provisions of and subject to the limitation of the tax laws of that State.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude the Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary, the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year

by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise registered and having the headquarters (i.e. effecting management) in a Contracting State from the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including:-

- (a) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises;
- (b) other activity directly connected with such transportation; and
- (c) the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly connected with such transportation.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

5. For the purposes of this Article interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 (Interest) shall not apply in relation to such interest.

6. Gains derived by an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the alienation of ships, aircraft or containers owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that State, shall be taxed only in that State.

ARTICLE 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of such liability by the exercise of a discretion or the making of an estimate by the competent authority of that State in cases which, from the information available to the competent authority of that State, it is not possible or not practicable to determine the income to be attributed to an enterprise, provided that law shall be applied, so far as the information available to the competent authority permits, consistently with the principles of this Article.

3. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to that enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividends :
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 :

- (a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :
 - (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State ; or
 - (ii) the Central Bank of the other Contracting State or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by the other Contracting State or political sub-division or local authority thereof ;
- (b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person other than a person referred to in sub-paragraph (a), who is a resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this regard by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

ROYALTIES AND FEES FOR INCLUDED SERVICES

1. Royalties and fees for included services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for included services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for included services the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for included services.

3. The term "royalties" in this Article means payments or credits, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for :

- (a) the use of, or the right to use any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right;
- (b) the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;

(c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information;

(d) the use of, or the right to use :

(i) motion picture films;

(ii) films or video tapes for use in connection with television; or

(iii) tapes for use in connection with radio broadcasting; or

(e) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to in this paragraph.

4. The term "fees for included services" in this Article means payments or credits, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for :

(a) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the application or enjoyment of, any such property or right as is mentioned in sub-paragraph (a) of paragraph (3), any such equipment as is mentioned in sub-paragraph (b) of paragraph (3), or any such knowledge or information as is mentioned in sub-paragraph (c) of paragraph (3);

(b) rendering of any technical or consultancy services (including the provision of technical or other personnel) if such services make available technical knowledge, experience, skill, knowledge or process or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.

5. The provision of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for included services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for included services arise, through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for included services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for included services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for included services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for included services was incurred, and such royalties or fees for included services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for included services having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13 TECHNICAL FEES

1. Technical fees arising in a Contracting State which are derived by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such technical fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State; but if the recipient is the beneficial owner of the technical fees, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the technical fees.

3. The term "technical fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature.

4. The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the technical fees, being a resident of a Contracting State in which the technical fees arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services, and the technical fees are effectively connected with such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Technical fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof, or a resident of that State. Where, however, the person paying the technical fees, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the technical fees was incurred, and such technical fees are borne by that permanent establishment, then such technical fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between of them and some other person, the amount of the technical fees paid, exceeds for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State due regards being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 14 CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in Article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the

alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 15 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 16 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant fiscal year; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article remuneration derived in respect of an employment exercised abroad on a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise shall be taxable only in the Contracting State

in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 17

DIRECTORS' FEES

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 18

INCOME EARNED BY ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

ARTICLE 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

ARTICLE 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on:

(a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and

(b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding US \$ 5,000 or its equivalent during any fiscal year, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefit of sub-paragraph (b) of paragraph (1) of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefit of sub-paragraph (b) of paragraph (1) of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

ARTICLE 22

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. Remuneration which a professor or teacher who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for a period not exceeding two years for the purpose of carrying out advanced study or research

or for teaching at a university, receives for such work shall not be taxed in that State, provided that such remuneration is derived by him from outside that State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be resident of a Contracting State if he is a resident in that Contracting State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

ARTICLE 23 OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 24 CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

CHAPTER IV METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

ARTICLE 25 AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the

respective Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

2. Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Cyprus, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Cyprus whether directly or by deduction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Cyprus. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Cyprus.

3. In the case of Cyprus, double taxation shall be avoided, subject to the provisions of the law of Cyprus regarding the allowance as a credit against Cyprus tax of tax payable in a territory outside Cyprus. Indian tax payable under the laws of India whether directly or by deduction, in respect of profits, income or gains from sources within India shall be allowed as a credit against any Cyprus tax payable in respect of that profit, income or gains. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to such income derived in India.

4. The tax payable in a Contracting State mentioned in paragraph 2 and paragraph 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development. For the purpose of paragraph 2 of Article 10 the amount of tax shall be deemed to be 10 per cent or 15 per cent, as the case may be, of the gross amount of dividend, for the purpose of paragraph 2 of Article 11, the amount of tax shall be deemed to be 10 per cent of the gross amount of interest and for the purpose of paragraph 2 of Article 12, the amount of tax shall be deemed to be 15 per cent of the gross amount of royalties and fees for included services and for the purpose of paragraph 2 of Article 13, the amount of tax shall be deemed to be 10 per cent of the gross amount of technical fees.

5. When in accordance with any provision of this Agreement income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 26 NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances. This provision shall not be construed as preventing

a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The document authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning

taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting States ;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

1. Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 30

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April, 1993 and in respect of capital which is held at the expiry of any previous year beginning on or after the first day of April, 1993,
- (b) in Cyprus, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January, 1993 and in respect of capital which is held at the expiry of any fiscal year beginning on or after the first day of April, 1993.

ARTICLE 31
TERMINATION

1. This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given and in respect of capital which is held at the expiry of any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.
- (b) in Cyprus, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice is given and in respect of capital which is held at

the expiry of any fiscal year next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

One in duplicate at Nairobi this 13th day of June, one thousand nine hundred and ninety four in English and Hindi both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts the English text shall be the operative one.

Sd/-

For the Government of
The Republic of INDIA.

Sd/-

For the Government of
The Republic of CYPRUS
[No. 9930/95/F. No. 503/4/89-FTB]
V. B. SRINIVASAN, Jt. Secy.